

समाज और सोशल मीडिया

यह एडटिओरियल 31 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित Social media: The new theatre of India's culture wars लेख पर आधारित है। इस लेख में समाज और शासन पर सोशल मीडिया के प्रभाव का विश्लेषण किया गया है।

संदर्भ

फेसबुक, ट्विटर जैसे अन्य सोशल मीडिया (Social Media- SM) प्लेटफार्मों की अभूतपूर्व वृद्धिलोकतंत्रों के कामकाज में एक दोधारी तलवार साबति हो रही है। एक ओर इसने सूचना तक पहुँच का लोकतांत्रकिरण किया है, वहीं दूसरी ओर इसने नई चुनौतियाँ भी पेश की हैं जो अब सीधे हमारे लोकतंत्र और लोगों पर प्रभाव डाल रही हैं।

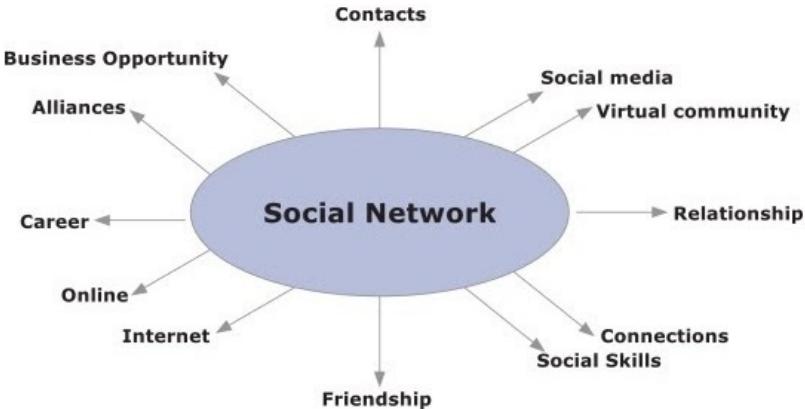
सोशल मीडिया का वसितार

- भारत में वर्ष 2019 तक 574 मिलियन सकरयि इंटरनेट उपयोगकरता थे।
- इंटरनेट प्रयोग करने के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है।
- एक अनुमान के अनुसार, दसिंबर 2020 तक भारत में लगभग 639 मिलियन सकरयि इंटरनेट उपयोगकरता होंगे।
- भारत के अधिकांश इंटरनेट उपयोगकरता मोबाइल फोन इंटरनेट उपयोगकरता है।
 - वर्ष 2019 में भारत में कुल डेटा (4G डेटा उपभोग के साथ) ट्रैफिक में 47% की वृद्धि हुई है। देश भर में खपत होने वाले कुल डेटा ट्रैफिक में 4G की भागीदारी 96% है जबकि 3G डेटा ट्रैफिक में 30% की उच्चतम गरिवट दर्ज की गई।

सोशल मीडिया के लाभ

- सूचना का लोकतंत्रीकरण
 - सोशल मीडिया जग्जान और व्यापक स्तर पर संचार सुविधाओं का लोकतंत्रीकरण करता है।
 - विश्व भर के अरबों लोगों ने अब सूचना को संरक्षित रखने और इसका प्रसार करने के पारंपरिक माध्यमों को चलन से लगभग बाहर कर दिया है। वे सरिफ इसके उपभोक्ता ही नहीं सामग्री के निर्माता और प्रसारकरता भी बन गए हैं।
- नए अवसर
 - आभासी दुनिया का उदय ऐसे लोगों को अपनी आवाज़ को मुखर करने का अवसर प्रदान करता है जिन्हें या तो अभी तक सुना नहीं जाता था अरथात् समाज का अपेक्षित आभासी दुनिया के माध्यम से ये लोग दूसरे लोगों से जुड़ते हैं और स्वयं को स्थापित कर पाते हैं। अगर व्यवसाय के रूप में देखें तो कई YouTubers का उदय इस घटना का परमाण है।
- व्यापक और विषम समुदाय
 - भौतिक समुदायों की तुलना में ऑनलाइन समुदाय भौगोलिक रूप से बहुत व्यापक और अधिक विषम है।
 - अतीत में भारत में कई समुदायों को सारवजनिक प्रवचनों में भाग लेने, खुद को संगठित करने तथा अपनी सोच और विचारों को आगे बढ़ाने की अनुभति नहीं थी। उनकी चित्ताओं, विचारों, अनुभवों, महत्वाकांक्षाओं और मांगों को काफी हद तक अनसुना कर जाता था।
- सस्ता और आसान
 - सोशल मीडिया के लिये आवश्यक कंटेंट के निर्माण में ईट और चूने पत्थर या कस्सी अन्य भौतिक पदार्थ की तुलना में कम निवेश की आवश्यकता होती है। यह अक्सर मृदु-कौशल से संचालित होता है।
 - प्रौद्योगिकी की सहायता से कोई भी व्यक्तिसिक्षम, प्रामाणिक, प्रभावी और मौलिक ऑनलाइन कंटेंट तैयार कर सकता है।

Dimensions of Social Network



■ आधिकारिक का मुकाबला

- सोशल मीडिया भी पारंपरिक खलिडायिंग के आधिकारिक या रविवायत का मुकाबला करने के लिये एक उपकरण के रूप में कारब्य करता है।
- इसने वाशिंगटन में ज्ञान का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान किया है, जिससे मुख्यधारा का मीडिया फर्जी खबरों और प्रचार-प्रसार के लिये गंभीर सार्वजनिक आलोचनाओं के घेरे में आ गया है।

■ दूरी समाप्त हो रही है

- सोशल मीडिया ने लोगों के बीच की दूरी को भी समाप्त करने का काम किया है।
- दोस्त और परिवार अब दूर होने के बावजूद भी व्हाट्सएप और अन्य ऐप के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं।

■ सरकार के साथ सीधा संवाद

- आज सोशल मीडिया ने आम लोगों को सरकार से सीधे बातचीत करने और सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने का अधिकार दिया है।
- आम लोग अपने सवाल या परेशानियों को रेलवे और अन्य मंत्रालयों को पोस्ट कर देते हैं, जो इन दिनों आम खबर हैं।

चुनौतियाँ

■ द्वेषपूर्ण भाषण और अफवाहें (Hate speech and Rumours)

- पछिले कुछ समय से कई मामलों में हसिंग और जान-माल की कष्टकारी लिये नफरत फैलाने वाले भाषण और अफवाहें जमिमेदार रहे हैं।
- हाल ही का एक मामला है जब महाराष्ट्र के पालघर के गढ़चिंग गाँव में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई।
- व्हाट्सएप मैसेज द्वारा यह अफवाह फैलाई गई किक्षेतर में तीन चोर चोरी कर रहे हैं, इस अफवाह के चलते गाँव के एक समूह ने तीनों यात्रियों को चोर समझकर उनकी हत्या कर दी थी। हस्तक्षेप करने वाले कई पुलिस कर्मियों पर भी गाँव वालों ने हमला कर दिया जिससे वे घायल हो गए।
- 2020 के दिल्ली दंगों में सोशल मीडिया पर हुए द्वेषपूर्ण भाषण की बड़ी भूमिका थी।

■ फेक न्यूज़

- वर्ष 2019 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 22 देशों में किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, 64% से अधिक भारतीय फर्जी खबरों का सामना करते हैं।
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों और व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग सेवाओं के माध्यम से प्रसारित एडिटिड इमेज, हेरा-फेरी वाले वीडियो और झूठे संदेशों की एक चौंका देने वाली संख्या मौजूद है जिससे गलत सूचनाओं और विश्वासनीय तथ्यों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है।

ऑनलाइन ट्रोलिंग

- ट्रोलिंग सोशल मीडिया का नया उप-उत्पाद है।
- कई बार लोग कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, लोगों को ट्रोल करना और धमकाना शुरू कर देते हैं जो उनके विचारों या आख्यानों से सहमत नहीं होते हैं।
- इसने कहीं व्यक्तिकी प्रतिष्ठित पर हमला करने वाले गुमनाम ट्रोल को भी बढ़ावा दिया है।

महलिया सुरक्षा

- महलियों को साइबर रेप और अन्य खतरों का सामना करना पड़ता है जो उनकी गरमियों को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।
- कभी-कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो को साइबर पर लीक कर देने की धमकी दी जाती है।
- कभी-कभी उनकी तस्वीरें और वीडियो लीक हो जाते हैं जिसके कारण उन्हें साइबर अपराध के लिये मजबूर किया जाता है।

आगे की राह

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)
 - कई सोशल मीडिया कंपनियों ने कुछ विशेष प्रकार की सामग्री को बढ़ावा देने या फिल्टर करने के लिये स्वचालित और मानव संचालित एडिटिड प्रक्रियाओं का मार्शिल तैयार किया है।

- ये AI इकाइयाँ स्वचालित रूप से कसी छवि या समाचार को साझा करने पर हर बार गलत रपोर्टिंग के खतरे को भांप लेंगी।
 - इस अभ्यास को और अधिक दृढ़ता के साथ कार्यान्वयन किया जाना चाहयि।
- **फर्जी सूचना के प्रतिवर्ग होना**
 - यह एक ऐसा तरीका है जहाँ फर्जी जानकारी के साथ कंटेंट की वास्तविक सुचना भी पोस्ट की जाती है ताकि उपयोगकर्ताओं को वास्तविक जानकारी और सच्चाई से अवगत कराया जा सके।
 - YouTube द्वारा लागू किया गया यह तरीका उपयोगकर्ताओं को नकली या घृणित सामग्री में किये गए भ्रामक दावों को खत्म कर देगा तथा सत्यापति और सुविधास्थिति जानकारी वाले लिंक पर क्लिक करने के लिये प्रोत्साहित करता है।
 - **वनियमन लाना**
 - सोशल मीडिया के लगातार बढ़ते दायरे का सामना करने के लिये एक संपूर्ण राष्ट्रीय कानून होना चाहयि।
 - इस संबंध में ज़मिमेदारी तय होनी चाहयि और कानूनी प्रावधान होने चाहयि।
 - **जन जागरूकता**
 - वर्तमान में देश को **डिजिटल साक्षर** बनाए जाने की ज़रूरत है।
 - एक ज़मिमेदार सोशल मीडिया का उपयोग कैसे किया जाए, इस विषय में देश के प्रत्येक स्कूल और कॉलेज एवं विशिष्टकर ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रक्रियण किया जाना चाहयि, जहाँ लोग उन्हें बेवकूफ बनाकर अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं।

कानूनी उपाय

- **भारत निरिवाचन आयोग (Election Commission of India- ECI)** ने चुनाव के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और गलत सूचना के प्रसार पर अंकुश लगाने के कई उपायों की घोषणा की थी।
- इसने राजनीतिक दलों के सोशल मीडिया कंटेंट को आदर्श आचार संहिता के दायरे में लाया गया और उम्मीदवारों को अपने सोशल मीडिया खातों तथा उनके संबंधित सोशल मीडिया अभियानों पर सभी खरचों का खुलासा करने के लिये कहा था।
- इसी प्रकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information & Broadcasting) की मीडिया विभिन्न सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्मों की गतिविधियों पर नज़र रखने में सरकार के विभिन्न संगठनों की सहायता करती रही है।
- इस तरह की गतिविधियों को सभी पैमानों और संस्थानों में प्रोत्साहित किया जाना चाहयि।

निषिकरण

- जैसा कि भारत एक निश्चानी राज्य नहीं है, इसलिये नजिता, बोलने और अभियक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार पर कोई गैर-कानूनी या असंवेदानकि जाँच नहीं होनी चाहयि जो प्रत्येक नागरकि का मौलिक अधिकार है। इसमें एक संतुलन होना चाहयि क्योंकि संविधान ने भाषण और अभियक्ति के अधिकार पर कई सीमाएँ लगाई हैं।
- बड़ी प्रौद्योगिकी फर्में, जिनके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, कंटेंट के संदर्भ में मध्यस्थिता कर सकती हैं और इस प्रकार लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती हैं।
- उन्हें और सभी को अपने कार्यों के लिये उत्तरदायी ठहराया जाना चाहयि, जिसके व्यापक सामाजिक प्रभाव होते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न: सोशल मीडिया लोकतंत्रों की कार्यप्रणाली में एक दोधारी तलवार है। वर्तमान विकास के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण करें।